>

Title: Need to implement Mediclaim Scheme in Andaman and Nicobar Islands.

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): सभापति महोदय, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में आजादी के पश्चात् से सरकारी कर्मचारियों, रिटायर्ड गवर्नमैंट सर्वेंट्स कैंसर, हार्ट, किडनी आदि से मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि हमारे पास अस्पताल और स्पैशलिस्ट्स नहीं थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई थी तब एक स्कीम बनी और अंडमान-निकोबार के सरकारी कर्मचारियों को बैनीफिट मिलना शुरू हुआ। आज दिल्ली में आईएएस, आईपीएस आदि सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमैंट के बाद स्पैशलिस्ट ट्रीटमैंट के लिए फैसीलिटी मिलती है। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में जो सरकारी कर्मचारी रिटायर हो जाता है, वह भी दिल्ली गवर्नमैंट की तरह सैंट्रल गवर्नमैंट इम्प्लाई है। इसलिए मैंने मई, 2010 को इसी पार्लियामेंट में नियम 377 के तहत मांग की कि गोवा गवर्नमैंट द्वारा 1989 में जो कानून बनाया गया था, उसी तरह अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में जो रिटायर्ड गवर्नमैंट सर्वेंट्स हैं और जिन लोगों की सालाना कमाई 3 लाख रुपये से कम है, ऐसे लोगों को स्पैशलिस्ट्स ट्रीटमैंट मिले। इस योजना का नाम मैडिक्लेम स्कीम है। इसी तरह अंडमान द्वीप समूह के 3 लाख रुपये सालाना की इनकम के नीचे द्वीपवासियों को तथा रिटायर्ड गवर्नमैंट सर्वेंट्स को पांच लाख रुपये सालाना इलाज का बैनीफिट मेनलैंड चेन्नई और कोलकाता में इलाज करने के लिए मिलेगा, यह स्कीम बनी और फाइल चलती रही। वर्ष 2010 में मैंने संसद में इस मुद्दे को रेज़ किया था। मैंने मांग की थी कि अंडमान-निकोबार द्वीप समूह का सालाना बजट 3200 करोड़ रुपये है जिसके अनुसार साल में एक आदमी पर 80 हजार रुपये का खर्च बैठता है और इस स्कीम के लिए केवल 15-20 करोड़ रुपये ही खर्च होंगे। मैंने वर्ष 2010 में मांग की, 2011 में टैक्नीकल बिड खोली गई, कमर्शियल बिड खोली गई और छ: महीने बाद फरवरी, 2012 आ गया। आज तक इस स्कीम की फाइल मूवमैंट में है। मेरी सरकार से मांग है, मुझे ऐसा सुनने में आया है कि प्रशासन अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में लाभार्थी के बीच में ब्रिटिश की तरह डिवाइस एंड रूल कर रहा है । द्वीप समूह के लोगों के नाम पर प्री 42, सैंटलर और नान-सैंटलर के आधार पर बहुत लाभार्थी को छोड़ने जा रहा है।

हमारी मांग है कि अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में जितने भी लोग हैं, जिनकी सालाना कमाई 3 लाख रुपये से नीचे है, जिन्होंने पंचायत और पार्लियामेंट में वोट दिया है, उन द्वीपवासियों तथा रिटायर्ड गवर्नमैंट सर्वेंट्स के लिए यह स्कीम लाकर तुंत इम्प्लीमैंट करें, क्योंकि राज्य हर साल रुपया सरैंडर कर रहे हैं। मैं कांग्रेस सरकार से मांग करूंगा कि अंडमान-निकोबार में एक्सप्रैस ट्रेन की तरह इस स्कीम को जल्दी इम्प्लीमैंट किया जाए।